Hour and Special mentions. Now, have you understood it?

SHRI SUKOMAL SEN : Now Members will prefer the zero hour, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : What will you prefer?

Shrimati Sarala Maheshwari.

You have seen her performance before, and you will see her performance now.

Increasing Foreign Media Dominance in India

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) : उपसभापति महोदया, हमारे देश में सूचना साम्राज्यवाद इन्फरमेशन इम्पैरेलिज्म के बढ़ते हुए खतरे की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं।

पश्चिम की दुनिया में आधुनिक प्रसार माध्यमों का शंहशाह कहलाने वाले कीथ रुपोर्ट मरडोक की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान हमारी सरकार के सर्वोच्च स्तरों तक से जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया उससे भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता के प्रति जागरूक सभी लोगों के कान खड़े हो गये हैं।

कुछ दिनों पहले तक इन्हीं मरडोक महोदय ने चीन के आधुनिक संचार माध्यमों पर अपना प्रभुत्व जमाने की योजना बनाई थी और इस बात की भरसक कोशिश की थी कि चीन सरकार भी पलक पावड़े बिछाकर श्री मान मरडोक को आतिथ्य प्रदान करे।

उन्होंने चीने के एक अखबार को खरीदने की पेशकश भी की थी लेकिन चीन में उन्हें टका सा जवाब मिला और अब वे यह कह रहे हैं कि जिस समय मैंने चीन के अखबार को खरीदने की बात सोची थी उस समय मैं कुछ ज्यादा ही पीया हुआ था। बहरहाल, चीन की सरकार ने कुछ दिन पहले ही मरडोक के स्टार टेलीविजन को लताड़ा था और उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर ले जाने का निर्देश दे दिया था। चीन की सरकार ने मरडोक की मेजबानी में कोई उत्साह नहीं दिखाया। तब दुनिया के लगभग 150 अखबारों और उतने ही टेलीविजन केन्द्रों के मालिक मरडोक ने भारत की ओर रुख किया है और भारत में जिस प्रकार उनका स्वागत किया गया उससे यह साफ है कि वह दिन दूर नहीं जब भारत के आधुनिक संचार माध्यमों पर मरडोक की तूती बोलेगी।

सिर्फ मरडोक ही नहीं दुनियां के और भी दूसरे बड़े-बड़े प्रसार माध्यमों के धत्रा सेठों ने भारत के बाजार को हथियाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी है।

लंदन का फाइनेन्शियल टाइम्स जिसे पश्चिमी दुनिया में वाणिज्यिक मामलों का सबसे बड़ा अखबार कहा जाता है उसने कलकत्ता के आनन्द बाजार समूह के साथ गठजोड़ करके "दी फाइनेन्शियल टाइम्स आफ इंडिया प्रा० लि०" के नाम से एक संयुक्त कंपनी का पंजीकरण कराया है।

चूंकि हमारे यहां पहले से ही "टाइम्स आफ इंडिया" ग्रुप ने फाइनेन्शियल टाइम्स के नाम से अखबारों के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक अखबार का पंजीकरण करा रखा है इसलिए इस नयी कम्पनी ने भारत में ट्रेड मार्क कानून के अन्तर्गत फाइनेन्शियल टाइम्स का रजिस्ट्रेशन कराया है। अर्थात् इस नयी कम्पनी का फाइनेंशियल टाइम्स कोई अखबार ना होकर उपभोक्ता सामग्री होगी। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि हमारे देश में अब तक चले आ रहे अखबारों के पंजीकरण संबंधी कानून को धत्ता बताने में वे कितनी दूर तक सफल होते हैं लेकिन एक बात साफ है कि यदि इस प्रकार के मसलों को देशी और विदेशी पूंजीपति के बीच की नोक-झोक का मसला बनाकर ही छोड़ दिया गया तो इससे विदेशी पूंजीपतियों के बढ़ते हुए वर्चस्व को कतई रोका नहीं जा सकता है।

पेप्सी कोला के विरुद्ध दफ्ती की तलवार मांजने वाले पारले एक्सपोर्ट्स कम्पनी ने खुद कोका कोला कंपनी के साथ जो शर्मनाक समझौता किया साफ पता चलता है कि पूंजीपति का धर्म सिर्फ मुनाफा और मुनाफे के अलावा और कुछ नहीं होता।

मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता बढ़ाने के नाम पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को हर क्षेत्र में काम करने की पूरी छूट दे दी गयी तो इनसे प्रतियोगिता नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों का एकछत्र साम्राज्य कायम होगा। आज दुनिया के सूचना बाजार की यही सबसे बड़ी सच्चाई है।

अमरीका तक की स्थिति यह है कि आज अमरीका की राजधानी में अंग्रेजी भाषा में सिर्फ अखबार छपता है जबकि भारत में बहुत थोड़े से लोग अंग्रेजी समझते हैं फिर भी अकेले इस राजधानी से 7 से ज्यादा अंग्रेजी दैनिक अखबार निकलते हैं। सिर्फ राजधानी का ही प्रश्न नहीं है अमरीका के जिन नगरों से दैनिक अखबार

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

निकलते है उनमें 98 प्रतिशत ऐसे अखबार हैं जिनका सिर्फ एक मालिक है, सिर्फ एक अखबार निकलता है। आप कल्पना कर सकते है कि हमारे देश की जो वैविध्यमयी संस्कृति है, जो विविधता है, उसका क्या होगा? अगर हमारे यहां से एक ही अखबार निकले तो सब का एकीकरण हो जाएगा और हमारी वैविध्यमयी संस्कृति विविध संस्कृति समाप्त हो जाएगी। उपसभापति महोदया, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर बड़ी बड़ी पूंजियों को सूचना और संस्कृति के क्षेत्र में खुल कर खेलने की अनुमति दे दी गई तो इससे हमारे सूचना जगत की विविधता समाप्त हो जाएगी, इजारेदारी बढ़ेगी। अगर यह इजारेदारी विदेशी कम्पनियों की होगी तो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जगत पर कितना भयावह असर होगा। इसकी आप आसानी से खुद कल्पना कर सकती है। सूचना और संस्कृति के क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इजारेदारी भारत की आर्थिक गुलामी का रास्ता प्रशस्त करेगी। इसलिए उपसभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूंगी, इस सदन के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि खिड़कियां खोलना तो जरूरी है लेकिन खिड़कियां और दरवाजे इस तरह से न खोलें कि हमारे पांव ज़मीन पर न टिकें और हम खुद आकाश में उड़ने लगें। हमारे पांव अपनी ज़मीन को न भूलें अपनी धरती को न भूलें अन्यथा हम अपनी संस्कृति अपनी अस्मिता सब को खो बैठेंगे। धन्यवाद।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): मैं श्रीमती सरला माहेश्वरी के कथन से अपने आप को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): मैं भी श्रीमती सरला माहेश्वरी के कथन से संबद्ध करती हूं।

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल (गुजरात): जब हम आकाश पर कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकेगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी तो भाषण बजा रही है **(व्यवधान)**

उपभापति: यह बोल रहे है कि आकाश पर हमारा कोई कब्जा नहीं है, कोई भी ट्रांसपोडर लगा कर के बीम कर सकता है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: यह व्यवस्था हमारे देश में नहीं है। मरडोक ने धमकी दी है कि हर देश को अपलिंकिंग की सुविधा देनी पड़ेगी। **(व्यवधान)**

Prime Minister's Request to U.S. President to make Pakistan sit with India on Kashmir

PROF. SAURIN BHATTACHARAYA (West Bengal): Madam Deputy Chairman, I would like to make a Special Mention which concerns something very important. The issue that I am going to raise concerns, on the face of it, Kashmir on which both the Houses of Parliament, yesterday, adopted a resolution, a very bold resolution at that. Over a long period of time, perhaps, this is the first occasion when it has been demanded straightway that Pakistan vacate Pok, that is, 'Occupied Kashmir'. Such a bold statement has not been made for a long time. Simulataneously, there is another point. We are all aware of the U.S. Administration's 'anti-Indian statements', so to say, as they have been characterised. Not only low-ranking officials like Ms. Robin Raphel but also the President of the mighty United States of America—the only super-power now in the whole of the world; perhaps, in the whole of the solar system—Mr. Bill Clinton, periodically continue with India-baiting, so to say. And, it was in response to such baiting that our Prime Minister, in his own usual fashion, without offending, suggested—rather, requested-this very President, Mr. Clinton, to make Pakistan sit with India on various disputes, as also Kashmir. Now, this is something which was totally unexpected from the Prime Minister of our country and a very diplomatic Prime Minister at that, like Mr. P.V. Narasimha Rao. When he requests President Clinton to make Pakistan sit with India on Kashmir, it is really inviting a third party to mediate in the matter of the conflict between India and Pakistan on Kashmir. This third party's intervention has been against the declared policy of the Government of India for a very long time and both earlier as External Affairs